

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 254 बेमेतरा, शनिवार 09 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

समाचार सार

स्विगी का इंस्टामार्ट की तेज ग्रोथ से बड़ी कमाई नईदिल्ली। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने शुक्रवार को बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में उसका घाटा घटकर 800 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 1,081 करोड़ था। कंपनी के क्रिक कॉमर्स कारोबार इंस्टामार्ट में लगातार ग्रोथ के चलते घाटे में कमी आई। कंपनी की आय बढ़कर 6,383 करोड़ हो गई। पिछली तिमाही में स्विगी ने 1,065 करोड़ का घाटा दर्ज किया था। स्विगी ने कहा कि उसके फूड डिलीवरी बिजनेस ने पिछले 15 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की।

चीनी युआन के बढ़ते प्रभाव ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता

नईदिल्ली। अमेरिकी सीनेटर्स के एक समूह ने अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी का दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव फिर से पेश किया है। सीनेटर्स ने चेतावनी दी है कि चीन, युआन के आस-पास एक दूसरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था बनाने की कोशिशें तेज कर रहा है। अमेरिकी सीनेटर्स के इस समूह में दोनों दलों के सांसद शामिल हैं। टेड बड और जॉन शाहीन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है। कि युआन को अंतरराष्ट्रीय बनाने की बीजिंग की कोशिश से अमेरिका और उसके साथियों के लिए आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है।

टाटा संस की लिस्टिंग बैठक 16 मई तक टाली नईदिल्ली। टाटा संस के मुख्य शेयरधारक सर दाराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने अपनी बोर्ड बैठकें 16 मई तक के लिए स्थगित कर दी हैं। इन बैठकों को गवर्नेस और कानूनी मुद्दों से जुड़ी चुनौतियों के कारण टाला गया है। ये बैठकें मूल रूप से 8 मई को निर्धारित थीं, जिनमें टाटा संस बोर्ड में ट्रस्टों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा होनी थी। सूत्रों के अनुसार, कुछ ट्रस्टी जिन्हें पहले ही निर्धारित बैठक में शामिल होना था, उन्हें बैठक शुरू होने से ठीक पहले रद्द होने की सूचना दी गई। बैठकें पहले 12 मई को भी निर्धारित की गई थीं, लेकिन बाद में स्थगित कर दी गईं।

सैंसेक्स 516 अंक टूटा निफ्टी 24,176 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट लेकर लाल निशान पर बंद हुए। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 516 अंक फिसल गया, जबकि निफ्टी-50 150 अंक टूटकर 24,176 पर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर घरेलू बाजार पर देखने को मिला। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 77,631 के स्तर पर खुला। दिन के कारोबार के दौरान इस इंडेक्स ने 77,647.44 के हाई और 77,146.43 के लो रेंज में ट्रेड किया।

भारत-पाक संघर्ष में चीन का कबूलनामा: नापाक साजिशों में दिया था साथ

बीजिंग ने ऑन-साइट सैन्य सपोर्ट की मानी बात

बीजिंग (ए)। चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उसने पिछले साल भारत के साथ चार दिवसीय संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को ऑन-साइट तकनीकी सहायता प्रदान की थी। यह खुलासा चीनी सरकारी मीडिया रिपोर्टों में सामने आया है, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस शुरू हो गई है। चीन के राज्य प्रसारक CCTV ने गुरुवार को एक इंटरव्यू प्रसारित किया, जिसमें एयरोस्पेस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना (AVIC) के चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर झांग हेंग ने इस दौरान पाकिस्तान को दी गई सहायता का जिक्र किया।

पाकिस्तान को चीनी लड़ाकू विमानों



का समर्थन- रिपोर्ट के अनुसार, झांग हेंग ने कहा कि उन्होंने पिछले साल मई में चार दिवसीय युद्ध के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी सहायता प्रदान की थी। पाकिस्तान की वायुसेना के पास चीन में निर्मित J-

10C E फाइटर जेट्स का बेड़ा मौजूद है, जिन्हें AVIC की एक सहायक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है।

युद्ध जैसी परिस्थितियों का किया सामना- सीसीटीवी को दिए गए बयान में

झांग हेंग ने बताया कि सपोर्ट बेस पर हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि लगातार फाइटर जेट्स की आवाज और एयर-रेड सायरन के बीच काम करना मानसिक और शारीरिक रूप से काफी कठिन था। उन्होंने यह भी कहा कि वहां का तापमान मई के महीने में ही 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था, जिससे स्थिति और भी कठिन हो गई थी।

तकनीकी सहयोग और साझेदारी पर जोर- झांग ने कहा कि उनकी टीम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि उपकरण अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें और बेहतर प्रदर्शन दें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ J-10CE विमान की क्षमता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक मजबूत कार्य संबंध और साझेदारी का भी प्रतीक था, जो उनके सहयोग के दौरान विकसित हुआ।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से गर्मी की छुट्टियां

नई दिल्ली (ए)। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का एलान कर दिया है। निदेशालय द्वारा जारी सकुलर के अनुसार, सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। इसके साथ ही नौवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष उपचारात्मक कक्षाएं भी आयोजित

की जाएंगी। इन कक्षाओं का उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई में कमजोर विषयों को मजबूत करना और उनको सीखने के स्तर में सुधार करना है। उपचारात्मक कक्षाएं 11 मई से 23 मई तक चलेंगी। ये कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित होंगी। शिक्षकों को सुबह 7:20 बजे से 11 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहना होगा।

एअर इंडिया सीईओ ने दिए खर्चों में कटौती के सख्त निर्देश

कर्मचारियों के लिए छंटनी का कोई खतरा नहीं

नई दिल्ली (ए)। देश के प्रमुख विमानन ब्रांड एअर इंडिया ने अपने मौजूदा वित्तीय संकट से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कंपनी प्रबंधन ने एक ओर जहां वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, वहीं दूसरी ओर अपने कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का ठोस भरोसा है। यह



कदम बताता है कि एयरलाइन बिना अपनी वर्कफोर्स को प्रभावित किए, खर्चों को कम करके अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। एअर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

कैपबेल विल्सन ने कंपनी में चल रहे वित्तीय संकट के मद्देनजर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से गैर-जरूरी खर्चों को निलंबित कर दें और भविष्य के अनावश्यक खर्चों को भी फिलहाल टाल दें। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए विल्सन ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कंपनी का पूरा ध्यान अब किसी भी तरह की बर्बादी और धन के रिसाव को खत्म करने पर होना चाहिए।

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच मुनाफावसूली हावी, सर्राफा बाजार में टूटे सोने-चांदी के दाम

नई दिल्ली (ए)। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच ताजा सैन्य हलचल का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि, इन तनावपूर्ण स्थितियों के बीच शुक्रवार को स्थानीय सर्राफा बाजार में एक अलग ही रुख देखने को मिला। निवेशकों द्वारा ऊंचे स्तरों पर की गई भारी मुनाफावसूली के कारण सोने और चांदी की कीमतों में नरमी दर्ज की गई है। यह स्थिति तब पैदा हुई है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों आसमान छू रही हैं और कूटनीतिक शांति की उम्मीदें लगातार कमजोर पड़ रही हैं।

स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम गिरे- अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली के स्थानीय बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 100 रुपये गिरकर 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। इसके पिछले कारोबारी सत्र में यह



कीमत 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) थी। इसी तरह, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव भी गुरुवार के 1,55,200 रुपये से फिसलकर 1,55,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। सफेद धातु यानी चांदी की बात करें तो लगातार चार दिनों की शानदार तेजी के बाद इसमें भी गिरावट का रुख रहा।

चांदी की कीमत 2,61,500 रुपये प्रति किलोग्राम के पिछले बंद भाव से गिरकर 2,61,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। गौरतलब है कि गुरुवार के सत्र में चांदी

की कीमतों में 7,000 रुपये प्रति किलोग्राम का भारी उछाल आया था, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली का सुरक्षित रास्ता चुना।

गिरावट के कारण और विशेषज्ञों की राय- इस व्यावसायिक परिदृश्य और कीमतों में आई नरमी को स्पष्ट करते हुए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कमोडिटीज विश्लेषक मानव मोदी ने बताया कि पिछले सत्र की तेज रैली के बाद सोने की कीमतों में यह मुनाफावसूली स्वाभाविक थी।

गवर्नर ने दिया सरकार बनाने का न्योता

विजय आज 11 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

बहुमत के लिए जुटाया समर्थन, कांग्रेस और वाम दलों का साथ

नई दिल्ली (ए)। तमिलनाडु में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। तमिलगना वेट्टो कजगम (टीवीके) के प्रमुख विजय शुक्रवार को तीसरी बार लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिले। विजय द्वारा समर्थन पत्र सौंपने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलैंकर ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। सूत्रों के अनुसार, यह मुलाकात संक्षिप्त रही। आज सुबह 11 बजे विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

कांग्रेस और वामपंथी दलों से समर्थन मिलने के बाद विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। वामपंथी दलों द्वारा बिना शर्त समर्थन देने के कुछ घंटों बाद विजय शुक्रवार को तीसरी बार राजभवन पहुंचे, उन्होंने सरकार बनाने के जरूरी आंकड़े का समर्थन पत्र सौंपा। टीवीके ने चुनाव में कुल 108 सीटें जीतकर मजबूत प्रदर्शन किया है। पार्टी प्रमुख विजय खुद दो सीटों से विजयी हुए हैं, जिसके चलते उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 सीटों का है। ऐसे में विजय को सरकार गठन के लिए अभी और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, भारतीय



कम्युनिस्ट पार्टी , वीसीके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI-M) के पास 2-2 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन टीवीके को पहले से मिला हुआ है।

इन सभी को जोड़ने के बाद भी विजय के पास कुल 118 विधायकों का समर्थन बनता है। माकपा ने आधिकारिक पत्र जारी कर TVK सरकार को समर्थन देने की घोषणा की, जबकि CPI ने स्थिर, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शासन के नाम पर सशर्त समर्थन दिया। इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पांच

विधायकों का समर्थन विजय को दिया है। इन सभी के समर्थन के बाद टीवीके और उसके सहयोगी विधायकों की कुल संख्या 118 हो जाती है। यह संख्या बहुमत के आंकड़े के करीब है। चुनाव में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, टीवीके के संस्थापक विजय को उन दो विधानसभा सीटों में से एक से इस्तीफा देना होगा, जिन पर उन्होंने जीत दर्ज की है। विजय ने चेन्नई की पेरांबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से चुनाव जीता है।

पुलिस सेवा में धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

बीजिंग। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पुलिस जैसी सार्वजनिक सेवा को किसी भी तरह से धोखाधड़ी का साधन नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने झारखंड पुलिस के एक कॉन्स्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय जांच में यदि पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत हों, तो उसे केवल औपचारिकताओं के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखना संस्थागत अनुशासन और जनता के विश्वास के लिए हानिकारक है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि यह मामला सिर्फ विभागीय गलती नहीं बल्कि गंभीर धोखाधड़ी से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई सही है, बल्कि आपराधिक जांच भी जरूरी है।

रायपुर पहुंची आरसीबीकी टीम, 10 मई को मुकाबला



रायपुर को 10 साल बाद आईपीएल में मैनो मेजबानी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में IPL 2026 के दो मैच होने वाले हैं, जिसके लिए RCB की टीम आज रायपुर पहुंच गई है। विराट कोहली के साथ ही अन्य खिलाड़ियों का रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया।

एयरपोर्ट से RCB की टीम मायरा रिसॉर्ट के लिए रवाना हो गई

है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। बता दें कि रायपुर को 10 साल बाद आईपीएल में मैनो की मेजबानी मिली है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैचों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी सेलिब्रिटीज से लेकर क्रिकेट फैंस के तैयार है।

रविवार यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस देखने

पहुंचेंगे। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और रोहित शर्मा की पत्नी रितिका पहुंच सकती हैं। इसके अलावा मुंबई इंडियंस फैंसचाई को स्पोर्ट करने के लिए अंबानी परिवार के पहुंचने के आसार हैं। बॉलीवुड हस्तियां भी मैच देखने आ सकती हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं।

सुरक्षा को लेकर पुलिस ने किए कड़े इंतजाम - राजधानी में एक ओर जहां क्रिकेट फैंस 10 और 13 मई को होने वाले मैच के लिए उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए हैं।

मुख्य सचिव विकासशील ने हाईलेवल मीटिंग ली थी, जिसके बाद से सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई हैं।



विचार–पक्ष

गैस-डीजल पर चुनाव के बाद झटका या वैश्विक असर?

कहने को ताजा बढोतरी का असर आबादी के एक छोटे हिस्से पर पड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन इतना तय है कि इसका दायरा बड़ा होने वाला है। पिछले करीब दो महीने से पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच वैश्विक स्तर पर जिस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, उसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की आपूर्ति बाधित होने के साथ ही महंगाई की रफ्तार भी तेज हुई है। ऐसे में भारत में भी महंगाई के बेलगाम होने की आशंका पहले से जताई जा रही थी। मगर ऐसा लगता है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही

सरकार ने जरूरी चीजों की कीमतों की लगाम को थाम के रखा हुआ था। गौरतलब है कि शुक्रवार को खाना पकाने के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में नौ सौ तिरानबे रुपए की भारी बढोतरी कर दी गई।वहीं चूँकि सामान्य घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित है, इसलिए पांच किलो गैस वाले छोटे सिलेंडर उपलब्ध तो कराए जा रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत में भी दो सौ इकसठ रुपए की बढोतरी कर दी गई और अब इसके लिए उपभोक्ताओं को आठ सौ दस रुपए पचास पैसे देने होंगे। इसके अलावा, विमान ईंधन और थोक

डीजल के मूल्य में भी वृद्धि की गई है।कहने को ताजा बढोतरी का असर आबादी के एक छोटे हिस्से पर पड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन इतना तय है कि इसका दायरा बड़ा होने वाला है। मसलन, केवल वाणिज्यिक गैस सिलेंडर को ही देखें, तो इसकी कीमत अब तीन हजार रुपए से भी ज्यादा हो गई है। जाहिर है, होटल, ढाबे या खाना पकाने का व्यवसाय करने वाले लोग अगर इसका उपयोग करेंगे, तो सीधे-सीधे इसका असर खाने-पीने की चीजों की कीमतों और लोगों की थाली पर पड़ेगा। संभव है कि कम आय वाले

लोगों के व्यवसाय पर भी इसका विपरीत असर पड़े।फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जिन कारणों से वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा करने को उचित ठहराया जा रहा है, उसी तरह के दूसरे कारण से आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आखिर छोटे सिलेंडर की कीमत में खासी बढोतरी कर ही दी गई है, जिसका उपयोग आमतौर पर प्रवासी मजदूर से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग करते हैं। इसी तरह, अब यह कहना मुश्किल है कि विमान ईंधन और थोक डीजल के

मूल्यों में वृद्धि केवल यहीं तक रुक जाएगी। अभी से आम उपयोग वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढोतरी की आशंका जताई जाने लगी है।जाहिर है, एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है, जिसमें महंगाई का दुश्क्रर आने वाले दिनों में और ज्यादा जटिल होता दिख रहा है। सवास्तौर पर डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद दुलाई का खर्च बढ़ेगा और इसके बाद चौतरफा महंगाई की मार सबके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। वैश्विक स्तर पर पसरी अस्थिरता की वजह से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हाल के दिनों में जो

सुस्ती देखी जा रही है, बाजार भी तेज उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है, उसमें एक बड़ी आबादी रोजी-रोजगार के सवालों से जूझ रही है।लगातार घटती क्रयशक्ति के दौर में महंगाई की मार का असर कितना गहरा हो सकता है, इसका बस अंदाजा ही लगाना या सकता है। सवाल है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से उपजे संकट के बावजूद सरकार ने करीब दो महीने तक तेल और गैस की कीमतों को कमावेश थाम कर रखा था और इनकी उपलब्धता के वैकल्पिक रास्ते निकाल रही थी.

धर्म शासित ईरानकी सामरिक-आक्रामकतैयारीव बढ़ती

सैन्य क्षमता गैर इस्लामिक देशों के लिए नसीहत है, कैसे?

भारत के निकटम पड़ोसी देश ईरान की सामरिक और आक्रामक तैयारी पूरी भारत-इजरायल समेत पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन गई है, क्योंकि उसने सीमित संसाधनों और भारी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ‘असममित युद्ध’ की ऐसी क्षमता विकसित कर ली, जिसने अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी सैन्य गठबंधनों को भी नई रणनीति बनाने और उससे आगे की सोचने पर मजबूर कर दिया है। यदि समय रहते इसकी काट विकसित नहीं की गई, तो अरब देशों पर अमेरिका के बाद चीन की पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि उसके साथ ईरान का सहयोगी रूस भी खड़ा है। वहीं, इस्लामिक मुल्क के नाम पर मुस्लिम देशों का अंदरूनी झुकाव भी उसकी ओर है, जिससे रूसी मित्रता और चीनी छल की चक्की में भारत के पिसने के आसार प्रबल हैं।

(कमलेश पांडे)
मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सि का संयुक्त मॉडल ही ईरानी सफलता का सूत्र है, क्योंकि ईरान ने केवल अपनी सेना पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार किया-हिजबुल्लाह, हूती और अन्य सहयोगी समूहों के माध्यम से उसने बहु-स्तरीय दबाव बनाया। यह ‘हाईब्रिड वारफेयर’ का आधुनिक मॉडल है।

भारत के निकटम पड़ोसी देश ईरान की सामरिक और आक्रामक तैयारी पूरी भारत-इजरायल समेत पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन गई है, क्योंकि उसने सीमित संसाधनों और भारी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ‘असममित युद्ध’ की ऐसी क्षमता विकसित कर ली, जिसने अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी सैन्य गठबंधनों को भी नई रणनीति बनाने और उससे आगे की सोचने पर मजबूर कर दिया है। यदि समय रहते इसकी काट विकसित नहीं की गई, तो अरब देशों पर अमेरिका के बाद चीन की पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि उसके साथ ईरान का सहयोगी रूस भी खड़ा है।

वहीं, इस्लामिक मुल्क के नाम पर मुस्लिम देशों का अंदरूनी झुकाव भी उसकी ओर है, जिससे रूसी मित्रता और चीनी छल की चक्की में भारत के पिसने के आसार प्रबल हैं। अनुभव बताता है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर ज्यादा भरोसा करता है और इस्लामिक नाटो का पक्षधर भी है, इसलिए ईरान के मामले में भारत की जरा सी रणनीतिक लापरवाही उसे चीनी चक्रव्यूह में धिरे अभिमुख्य वाली कर देगी, क्योंकि भारत की हिन्दू विरोधी मुस्लिम राजनीति के आर्थिक स्रोत भी इस्लामिक मुल्कों से ही जुड़े बताए जाते हैं।

पहले ईरान से भारत-इजरायल समेत शेष दुनिया को मिलने वाली प्रमुख सामरिक सीखें निम्नलिखित हैं-
पहला, आत्मनिर्भर सैन्य उत्पादन सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि ईरान ने दशकों के प्रतिबंधों के बावजूद अपने मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तंत्र को घरेलू स्तर पर विकसित किया। आज उसके पास मध्य-पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार माना जाता है। चूँकि वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ईरान ने लोकतंत्र की बजाय समानांतर कट्टर धार्मिक तंत्र विकसित कर लिया, जिससे भारत को अवश्य सीखने की जरूरत है। क्योंकि ईरान की इस नीति का संदेश स्पष्ट है- जो देश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, वही लंबे संघर्ष में टिकेगा।

दूसरा, ड्रोन युद्ध ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है, क्योंकि ईरान ने कम लागत वाले ड्रोन को रणनीतिक हथियार बना दिया। उसने दिखाया कि हजारों करोड़ की एयर डिफेंस प्रणाली को सस्ते ड्रोन झुंड से भी चुनौती दी जा सकती है। इसलिए आज अमेरिका तक स्वीकार कर रहा है कि महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों के मुकाबले सस्ते ड्रोन कास्ट इम्बैलेस पैदा कर रहे हैं।

तीसरा, युद्ध केवल हथियार नहीं, धैर्य से जीता जाता है, यही बात ईरान ने दुनिया को सिखलाया है। जिस तरह से उसने अमेरिका-इजरायल के यौद्धिक गुरूर को तोड़ा है, वह शोध का विषय है, क्योंकि रूस-चीन के नैतिक मदद से उसने यह सफलता हासिल की है। ईरान ने प्रत्यक्ष युद्ध से अधिक लंबी थकाऊ लड़ाई की रणनीति अपनाई। उसका उद्देश्य

तत्काल जीत नहीं, बल्कि विरोधी की आर्थिक, सैन्य और मनोवैज्ञानिक क्षमता को थकाना रहा। यह आधुनिक युद्ध की नई वास्तविकता है- हर युद्ध बेलेटेजिंग नहीं होता; कई युद्ध विरोधी को थकाकर जीते जाते हैं।

चौथा, कमांड सिस्टम का बैकअप अत्यंत जरूरी होता है, ताकि भारी हमलों और शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के बावजूद ईरान का सैन्य कमांड ढांचा पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ। उसने पहले से वैकल्पिक नेतृत्व और विकेंद्रीकृत कमांड संरचना तैयार कर रखी थी। यह हर राष्ट्र के लिए बड़ा संदेश है कि-युद्ध में नेतृत्व का विकल्प पहले से तैयार होना चाहिए।

पांचवां, मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सि का संयुक्त मॉडल ही ईरानी सफलता का सूत्र है, क्योंकि ईरान ने केवल अपनी सेना पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार किया-हिजबुल्लाह, हूती और अन्य सहयोगी समूहों के माध्यम से उसने बहु-स्तरीय दबाव बनाया। यह हाईब्रिड वारफेयर का आधुनिक मॉडल है।

छठा, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की शक्ति विकसित करके आक्रमणकारियों को तोड़ना ईरानी दूरदर्शिता का ही तकाजा है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का प्रभाव पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है। इसी कारण अमेरिका और पश्चिम लगातार उस क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाते रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है-भूगोल भी उतना ही बड़ा हथियार है जितना मिसाइल।

सातवां, तकनीकी युद्ध में सस्ता हथियार भी निर्णायक होता है, यह ईरान ने साबित कर दिया है। ईरान ने दिखाया कि हर युद्ध अत्याधुनिक स्ट्रीट्स फाइटर से नहीं जीता जाता। कभी-कभी सस्ती, तेज और बड़ी संख्या में उपलब्ध तकनीक अधिक प्रभावी होती है।

निष्कर्षतः-ईरान की तैयारी गैर इस्लामिक दुनिया को यह सिखाती है कि आधुनिक युद्ध केवल परमाणु बम या महंगे लड़ाकू विमानों से नहीं लड़े जाते। आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, ड्रोन तकनीक, मिसाइल क्षमता, साइबर-रणनीति, वैकल्पिक नेतृत्व और मनोवैज्ञानिक युद्ध-ये सब मिलकर किसी राष्ट्र को सामरिक शक्ति बनाते हैं। इसीलिए आज अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन और भारत समेत दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां भी ईरानी मॉडल का गंभीर अध्ययन कर रही हैं। एक बात और, ईरान के सामरिक मॉडल से भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि केवल पारंपरिक सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं होती; दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय प्रतिरोध क्षमता विकसित करनी पड़ती है। विशेषकर तब, जब भारत को दशकों से पाकिस्तान प्रयोजित आतंकवाद, कट्टरपंथ और चीन-पाकिस्तान जैसे सामरिक गठबंधनों का सामना करना पड़ रहा हो।

हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस्लामिक देश एक समान इकाई नहीं हैं। भारत के कई इस्लामी देशों-जैसे संयुक्त अरब अमीरात यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और कतर-से मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। भारत की मुख्य सुरक्षा चुनौती कुछ कट्टरपंथी नेटवर्क, आतंकवादी संरचनाओं और शत्रुतापूर्ण राज्य-नीतियों से रही है, न कि सम्पूर्ण इस्लामी विश्व से। भारत के लिए प्रमुख सबक इस प्रकार हैं

पहला, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन ही निर्णायक सुरक्षा- ईरान ने प्रतिबंधों के बावजूद अपने ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तंत्र विकसित किए। भारत के लिए इसका अर्थ है कि विदेशी हथियारों पर अत्यधिक निर्भरता घटानी होगी। आत्मनिर्भर भारत को केवल नारा नहीं, बल्कि युद्धकालीन औद्योगिक क्षमता बनाना होगा।

दूसरा, सस्ते ड्रोन बनाम महंगी सुरक्षा- ईरान ने दिखाया कि कम लागत वाले ड्रोन भी महंगी एयर डिफेंस प्रणाली को चुनौती दे सकते हैं। भारत को सीमा सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी अभियानों और समुद्री निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी ड्रोन नेटवर्क बनाना होगा।

तीसरा, मोजेक डिफेंस मॉडल- ईरान की विकेंद्रीकृत सैन्य संरचना-जहां शीर्ष नेतृत्व पर हमला होने के बाद भी स्थानीय इकाइयाँ लड़ती रहती हैं-भारत के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। भारत को भी साइबर, सीमा, वायु और समुद्री मोर्चों पर ऐसी बहुस्तरीय कमांड संरचना विकसित करनी होगी जो आंचानक हमले में भी सक्रिय रहे।

चौथा, केवल सीमा नहीं, मनोवैज्ञानिक युद्ध भी- आधुनिक संघर्ष अब केवल बंदूक और मिसाइल का नहीं, बल्कि सूचना और नैरेटिव का भी है। भारत को फेक न्यूज, साइबर-प्रोपेगंडा और धार्मिक कट्टरता आधारित डिजिटल अभियानों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा ढांचा मजबूत करना होगा।

पांचवां, लंबी लड़ाई की तैयारी- ईरान ने दिखाया कि ‘वार आफ आर्टीशन’ यानी विरोधी को धीरे-धीरे थकाना भी रणनीति हो सकती है। भारत को सीमित अवधि के युद्ध की सोच से आगे जाकर लंबे संघर्ष, आपूर्ति शृंखला और गोला-बारूद भंडारण की तैयारी करनी होगी।

छठा, ऊर्जा सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा है-यदि पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध होता है, तो भारत की तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसलिए सामरिक तेल भंडार, वैकल्पिक ऊर्जा और समुद्री मार्ग सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। सातवां, संयुक्त युद्ध की तैयारी- आज युद्ध भूमि, समुद्र और आकाश तक सीमित नहीं है; साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र भी युद्धक्षेत्र बन चुके हैं। भारत को थिएटर कमांड, एआई आधारित निगरानी और संयुक्त सैन्य संचालन को तेज करना होगा।

आठवां, राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ी सुरक्षा- ईरान के उदाहरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि बाहरी दबाव के समय आंतरिक सामाजिक एकता निर्णायक होती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में सांप्रदायिक विभाजन, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक अविश्वास राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं।

निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि भविष्य का युद्ध केवल सेना नहीं, बल्कि पूरा राष्ट्र लड़ता है-तकनीक, अर्थव्यवस्था, साइबर क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक एकता और मनोवैज्ञानिक दृढ़ता-सब मिलकर राष्ट्रीय शक्ति बनाते हैं। ईरान ने दुनिया को यह दिखाया कि सीमित संसाधनों वाला राष्ट्र भी यदि आत्मनिर्भर, संगठित और रणनीतिक रूप से धैर्यवान हो, तो वह कहीं बड़ी शक्तियों को भी लंबे समय तक चुनौती दे सकता है।

भारत के निकटम पड़ोसी देश ईरान की सामरिक और आक्रामक तैयारी पूरी भारत-इजरायल समेत पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन गई है, क्योंकि उसने सीमित संसाधनों और भारी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ‘असममित युद्ध’ की ऐसी क्षमता विकसित कर ली, जिसने अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी सैन्य गठबंधनों को भी नई रणनीति बनाने और उससे आगे की सोचने पर मजबूर कर दिया है। यदि समय रहते इसकी काट विकसित नहीं की गई, तो अरब देशों पर अमेरिका के बाद चीन की पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि उसके साथ ईरान का सहयोगी रूस भी खड़ा है। वहीं, इस्लामिक मुल्क के नाम पर मुस्लिम देशों का अंदरूनी झुकाव भी उसकी ओर है, जिससे रूसी मित्रता और चीनी छल की चक्की में भारत के पिसने के आसार प्रबल हैं।

(कमलेश पांडे)
मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सि का संयुक्त मॉडल ही ईरानी सफलता का सूत्र है, क्योंकि ईरान ने केवल अपनी सेना पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार किया-हिजबुल्लाह, हूती और अन्य सहयोगी समूहों के माध्यम से उसने बहु-स्तरीय दबाव बनाया। यह ‘हाईब्रिड वारफेयर’ का आधुनिक मॉडल है।

भारत के निकटम पड़ोसी देश ईरान की सामरिक और आक्रामक तैयारी पूरी भारत-इजरायल समेत पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन गई है, क्योंकि उसने सीमित संसाधनों और भारी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ‘असममित युद्ध’ की ऐसी क्षमता विकसित कर ली, जिसने अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी सैन्य गठबंधनों को भी नई रणनीति बनाने और उससे आगे की सोचने पर मजबूर कर दिया है। यदि समय रहते इसकी काट विकसित नहीं की गई, तो अरब देशों पर अमेरिका के बाद चीन की पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि उसके साथ ईरान का सहयोगी रूस भी खड़ा है। वहीं, इस्लामिक मुल्क के नाम पर मुस्लिम देशों का अंदरूनी झुकाव भी उसकी ओर है, जिससे रूसी मित्रता और चीनी छल की चक्की में भारत के पिसने के आसार प्रबल हैं। अनुभव बताता है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर ज्यादा भरोसा करता है और इस्लामिक नाटो का पक्षधर भी है, इसलिए ईरान के मामले में भारत की जरा सी रणनीतिक लापरवाही उसे चीनी चक्रव्यूह में धिरे अभिमुख्य वाली कर देगी, क्योंकि भारत की हिन्दू विरोधी मुस्लिम राजनीति के आर्थिक स्रोत भी इस्लामिक मुल्कों से ही जुड़े बताए जाते हैं। पहले ईरान से भारत-इजरायल समेत शेष दुनिया को मिलने वाली प्रमुख सामरिक सीखें निम्नलिखित हैं-
पहला, आत्मनिर्भर सैन्य उत्पादन सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि ईरान ने दशकों के प्रतिबंधों के बावजूद अपने मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तंत्र को घरेलू स्तर पर विकसित किया। आज उसके पास मध्य-पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार माना जाता है। चूँकि वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ईरान ने लोकतंत्र की बजाय समानांतर कट्टर धार्मिक तंत्र विकसित कर लिया, जिससे भारत को अवश्य सीखने की जरूरत है। क्योंकि ईरान की इस नीति का संदेश स्पष्ट है- जो देश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, वही लंबे संघर्ष में टिकेगा।
दूसरा, ड्रोन युद्ध ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है, क्योंकि ईरान ने कम लागत वाले ड्रोन को रणनीतिक हथियार बना दिया। उसने दिखाया कि हजारों करोड़ की एयर डिफेंस प्रणाली को सस्ते ड्रोन झुंड से भी चुनौती दी जा सकती है। इसलिए आज अमेरिका तक स्वीकार कर रहा है कि महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों के मुकाबले सस्ते ड्रोन कास्ट इम्बैलेस पैदा कर रहे हैं।
तीसरा, युद्ध केवल हथियार नहीं, धैर्य से जीता जाता है, यही बात ईरान ने दुनिया को सिखलाया है। जिस तरह से उसने अमेरिका-इजरायल के यौद्धिक गुरूर को तोड़ा है, वह शोध का विषय है, क्योंकि रूस-चीन के नैतिक मदद से उसने यह सफलता हासिल की है। ईरान ने प्रत्यक्ष युद्ध से अधिक लंबी थकाऊ लड़ाई की रणनीति अपनाई। उसका उद्देश्य

तत्काल जीत नहीं, बल्कि विरोधी की आर्थिक, सैन्य और मनोवैज्ञानिक क्षमता को थकाना रहा। यह आधुनिक युद्ध की नई वास्तविकता है- हर युद्ध बेलेटेजिंग नहीं होता; कई युद्ध विरोधी को थकाकर जीते जाते हैं।
चौथा, कमांड सिस्टम का बैकअप अत्यंत जरूरी होता है, ताकि भारी हमलों और शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के बावजूद ईरान का सैन्य कमांड ढांचा पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ। उसने पहले से वैकल्पिक नेतृत्व और विकेंद्रीकृत कमांड संरचना तैयार कर रखी थी। यह हर राष्ट्र के लिए बड़ा संदेश है कि-युद्ध में नेतृत्व का विकल्प पहले से तैयार होना चाहिए।
पांचवां, मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सि का संयुक्त मॉडल ही ईरानी सफलता का सूत्र है, क्योंकि ईरान ने केवल अपनी सेना पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार किया-हिजबुल्लाह, हूती और अन्य सहयोगी समूहों के माध्यम से उसने बहु-स्तरीय दबाव बनाया। यह हाईब्रिड वारफेयर का आधुनिक मॉडल है।
छठा, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की शक्ति विकसित करके आक्रमणकारियों को तोड़ना ईरानी दूरदर्शिता का ही तकाजा है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का प्रभाव पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है। इसी कारण अमेरिका और पश्चिम लगातार उस क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाते रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है-भूगोल भी उतना ही बड़ा हथियार है जितना मिसाइल।
सातवां, तकनीकी युद्ध में सस्ता हथियार भी निर्णायक होता है, यह ईरान ने साबित कर दिया है। ईरान ने दिखाया कि हर युद्ध अत्याधुनिक स्ट्रीट्स फाइटर से नहीं जीता जाता। कभी-कभी सस्ती, तेज और बड़ी संख्या में उपलब्ध तकनीक अधिक प्रभावी होती है।
निष्कर्षतः-ईरान की तैयारी गैर इस्लामिक दुनिया को यह सिखाती है कि आधुनिक युद्ध केवल परमाणु बम या महंगे लड़ाकू विमानों से नहीं लड़े जाते। आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, ड्रोन तकनीक, मिसाइल क्षमता, साइबर-रणनीति, वैकल्पिक नेतृत्व और मनोवैज्ञानिक युद्ध-ये सब मिलकर किसी राष्ट्र को सामरिक शक्ति बनाते हैं। इसीलिए आज अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन और भारत समेत दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां भी ईरानी मॉडल का गंभीर अध्ययन कर रही हैं। एक बात और, ईरान के सामरिक मॉडल से भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि केवल पारंपरिक सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं होती; दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय प्रतिरोध क्षमता विकसित करनी पड़ती है। विशेषकर तब, जब भारत को दशकों से पाकिस्तान प्रयोजित आतंकवाद, कट्टरपंथ और चीन-पाकिस्तान जैसे सामरिक गठबंधनों का सामना करना पड़ रहा हो।
हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस्लामिक देश एक समान इकाई नहीं हैं। भारत के कई इस्लामी देशों-जैसे संयुक्त अरब अमीरात यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और कतर-से मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। भारत की मुख्य सुरक्षा चुनौती कुछ कट्टरपंथी नेटवर्क, आतंकवादी संरचनाओं और शत्रुतापूर्ण राज्य-नीतियों से रही है, न कि सम्पूर्ण इस्लामी विश्व से। भारत के लिए प्रमुख सबक इस प्रकार हैं

पहला, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन ही निर्णायक सुरक्षा- ईरान ने प्रतिबंधों के बावजूद अपने ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तंत्र विकसित किए। भारत के लिए इसका अर्थ है कि विदेशी हथियारों पर अत्यधिक निर्भरता घटानी होगी। आत्मनिर्भर भारत को केवल नारा नहीं, बल्कि युद्धकालीन औद्योगिक क्षमता बनाना होगा।

दूसरा, सस्ते ड्रोन बनाम महंगी सुरक्षा- ईरान ने दिखाया कि कम लागत वाले ड्रोन भी महंगी एयर डिफेंस प्रणाली को चुनौती दे सकते हैं। भारत को सीमा सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी अभियानों और समुद्री निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी ड्रोन नेटवर्क बनाना होगा।
तीसरा, मोजेक डिफेंस मॉडल- ईरान की विकेंद्रीकृत सैन्य संरचना-जहां शीर्ष नेतृत्व पर हमला होने के बाद भी स्थानीय इकाइयाँ लड़ती रहती हैं-भारत के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। भारत को भी साइबर, सीमा, वायु और समुद्री मोर्चों पर ऐसी बहुस्तरीय कमांड संरचना विकसित करनी होगी जो आंचानक हमले में भी सक्रिय रहे।
चौथा, केवल सीमा नहीं, मनोवैज्ञानिक युद्ध भी- आधुनिक संघर्ष अब केवल बंदूक और मिसाइल का नहीं, बल्कि सूचना और नैरेटिव का भी है। भारत को फेक न्यूज, साइबर-प्रोपेगंडा और धार्मिक कट्टरता आधारित डिजिटल अभियानों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा ढांचा मजबूत करना होगा।
पांचवां, लंबी लड़ाई की तैयारी- ईरान ने दिखाया कि ‘वार आफ आर्टीशन’ यानी विरोधी को धीरे-धीरे थकाना भी रणनीति हो सकती है। भारत को सीमित अवधि के युद्ध की सोच से आगे जाकर लंबे संघर्ष, आपूर्ति शृंखला और गोला-बारूद भंडारण की तैयारी करनी होगी।
छठा, ऊर्जा सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा है-यदि पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध होता है, तो भारत की तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसलिए सामरिक तेल भंडार, वैकल्पिक ऊर्जा और समुद्री मार्ग सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है।
सातवां, संयुक्त युद्ध की तैयारी- आज युद्ध भूमि, समुद्र और आकाश तक सीमित नहीं है; साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र भी युद्धक्षेत्र बन चुके हैं। भारत को थिएटर कमांड, एआई आधारित निगरानी और संयुक्त सैन्य संचालन को तेज करना होगा।
आठवां, राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ी सुरक्षा- ईरान के उदाहरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि बाहरी दबाव के समय आंतरिक सामाजिक एकता निर्णायक होती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में सांप्रदायिक विभाजन, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक अविश्वास राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं।

निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि भविष्य का युद्ध केवल सेना नहीं, बल्कि पूरा राष्ट्र लड़ता है-तकनीक, अर्थव्यवस्था, साइबर क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक एकता और मनोवैज्ञानिक दृढ़ता-सब मिलकर राष्ट्रीय शक्ति बनाते हैं। ईरान ने दुनिया को यह दिखाया कि सीमित संसाधनों वाला राष्ट्र भी यदि आत्मनिर्भर, संगठित और रणनीतिक रूप से धैर्यवान हो, तो वह कहीं बड़ी शक्तियों को भी लंबे समय तक चुनौती दे सकता है।

भारत के निकटम पड़ोसी देश ईरान की सामरिक और आक्रामक तैयारी पूरी भारत-इजरायल समेत पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन गई है, क्योंकि उसने सीमित संसाधनों और भारी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ‘असममित युद्ध’ की ऐसी क्षमता विकसित कर ली, जिसने अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी सैन्य गठबंधनों को भी नई रणनीति बनाने और उससे आगे की सोचने पर मजबूर कर दिया है। यदि समय रहते इसकी काट विकसित नहीं की गई, तो अरब देशों पर अमेरिका के बाद चीन की पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि उसके साथ ईरान का सहयोगी रूस भी खड़ा है। वहीं, इस्लामिक मुल्क के नाम पर मुस्लिम देशों का अंदरूनी झुकाव भी उसकी ओर है, जिससे रूसी मित्रता और चीनी छल की चक्की में भारत के पिसने के आसार प्रबल हैं। अनुभव बताता है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर ज्यादा भरोसा करता है और इस्लामिक नाटो का पक्षधर भी है, इसलिए ईरान के मामले में भारत की जरा सी रणनीतिक लापरवाही उसे चीनी चक्रव्यूह में धिरे अभिमुख्य वाली कर देगी, क्योंकि भारत की हिन्दू विरोधी मुस्लिम राजनीति के आर्थिक स्रोत भी इस्लामिक मुल्कों से ही जुड़े बताए जाते हैं। पहले ईरान से भारत-इजरायल समेत शेष दुनिया को मिलने वाली प्रमुख सामरिक सीखें निम्नलिखित हैं-
पहला, आत्मनिर्भर सैन्य उत्पादन सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि ईरान ने दशकों के प्रतिबंधों के बावजूद अपने मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तंत्र को घरेलू स्तर पर विकसित किया। आज उसके पास मध्य-पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार माना जाता है। चूँकि वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ईरान ने लोकतंत्र की बजाय समानांतर कट्टर धार्मिक तंत्र विकसित कर लिया, जिससे भारत को अवश्य सीखने की जरूरत है। क्योंकि ईरान की इस नीति का संदेश स्पष्ट है- जो देश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, वही लंबे संघर्ष में टिकेगा।
दूसरा, ड्रोन युद्ध ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है, क्योंकि ईरान ने कम लागत वाले ड्रोन को रणनीतिक हथियार बना दिया। उसने दिखाया कि हजारों करोड़ की एयर डिफेंस प्रणाली को सस्ते ड्रोन झुंड से भी चुनौती दी जा सकती है। इसलिए आज अमेरिका तक स्वीकार कर रहा है कि महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों के मुकाबले सस्ते ड्रोन कास्ट इम्बैलेस पैदा कर रहे हैं।
तीसरा, युद्ध केवल हथियार नहीं, धैर्य से जीता जाता है, यही बात ईरान ने दुनिया को सिखलाया है। जिस तरह से उसने अमेरिका-इजरायल के यौद्धिक गुरूर को तोड़ा है, वह शोध का विषय है, क्योंकि रूस-चीन के नैतिक मदद से उसने यह सफलता हासिल की है। ईरान ने प्रत्यक्ष युद्ध से अधिक लंबी थकाऊ लड़ाई की रणनीति अपनाई। उसका उद्देश्य

तत्काल जीत नहीं, बल्कि विरोधी की आर्थिक, सैन्य और मनोवैज्ञानिक क्षमता को थकाना रहा। यह आधुनिक युद्ध की नई वास्तविकता है- हर युद्ध बेलेटेजिंग नहीं होता; कई युद्ध विरोधी को थकाकर जीते जाते हैं।

चौथा, कमांड सिस्टम का बैकअप अत्यंत जरूरी होता है, ताकि भारी हमलों और शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के बावजूद ईरान का सैन्य कमांड ढांचा पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ। उसने पहले से वैकल्पिक नेतृत्व और विकेंद्रीकृत कमांड संरचना तैयार कर रखी थी। यह हर राष्ट्र के लिए बड़ा संदेश है कि-युद्ध में नेतृत्व का विकल्प पहले से तैयार होना चाहिए।

पांचवां, मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सि का संयुक्त मॉडल ही ईरानी सफलता का सूत्र है, क्योंकि ईरान ने केवल अपनी सेना पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार किया-हिजबुल्लाह, हूती और अन्य सहयोगी समूहों के माध्यम से उसने बहु-स्तरीय दबाव बनाया। यह ‘हाईब्रिड वारफेयर’ का आधुनिक मॉडल है।

‘थलापति’ से ‘मुधलवन’ तक- कैसे विजय ने तमिलनाडु की सत्ता का रुख मोड़ दिया

(रेनु तिवारी)

विजय का चुनाव प्रचार पारंपरिक राजनीति से बिच्छुल अलग था। जहाँ अन्य दल रैलियों और रोड-शो पर करोड़ों खर्च कर रहे थे, विजय ने एक ‘साइलेंट वारियर’ की तरह काम किया।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया है। जब अभिनेता विजय ने तमिलनाा वेत्री कण्णम (टीवीके) की स्थापना की थी, तो कई विश्लेषकों ने उन्हें द्रविड़ राजनीति के दो दिग्गजों (डीएमके और एआईएडीएमके) के सामने कमतर आंका था। लेकिन आज, विजय न केवल एक ‘स्टार’ बल्कि तमिलनाडु के ‘मुधलवन’ (मुख्यमंत्री) के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

विजय का चुनाव प्रचार पारंपरिक राजनीति से बिच्छुल अलग था। जहाँ अन्य दल रैलियों और रोड-शो पर करोड़ों खर्च कर रहे थे, विजय ने एक ‘साइलेंट वारियर’ की तरह काम किया-

सोशल मीडिया का जादू- उन्होंने न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर न ही टीवी इंटरव्यू दिए। इसके बजाय, उन्होंने सीधे सोशल मीडिया के जरिए जनता से संवाद किया। विजय मामा और नन्हें ब्रांड एंबेसडर-विजय ने चतुराई से बच्चों और किशोरों को अपना ‘नानबा’ (दोस्त) बनाया। ‘विजय मामा’ के संबोधन ने बच्चों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपने माता-पिता को टीवीके को वोट देने के लिए प्रेरित किया।

साधारण में भव्यता-कभी तंग गलियों में साइकिल चलाता तो कभी फिल्म समारोहों में छोटी कहालियों के जरिए सत्ता पर तीखे प्रहार करना-विजय के हर कदम ने जनता के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया। चुनाव प्रचार के दौरान अभिनेता ने असामान्य रूप से किशोरों और बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि वे उनके माता-पिता को टीवीके के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर सकें। जब मतदान का आंकड़ा 85 फीसदी के

पार चला गया, तब विजय ने खुद को ‘विजय मामा’ कहते हुए खास तौर पर ‘कुट्टी, नानबा, नानबी’ (बच्चों और दोस्तों) को संबोधित किया और अभिभावकों को टीवीके के समर्थन के लिए मनाने के वास्ते उनका आभार जताया। यही नहीं, उन्होंने द्रविड़ विचारधारा और तमिल राष्ट्रवाद के तत्वों को कुशलतापूर्वक संयोजित करते हुए अपनी पार्टी की विचारधारा स्पष्ट की।

विजय ने हमेशा से ही लीक से हटकर कदम उठाए। एक दिन वह अप्र

कार्ड का वितरण।

स्वास्थ्य एवं सहायता: दिव्यांगजनों को भ्रूषण यंत्र एवं टीबी मरीजों को पोषण आहार केट प्रदान की गई। प्रतिभा सम्मान: क्षेत्र के कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र-छात्राओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाली अंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।

